



NHRC reconstitutes core group of human rights defenders, NGOs

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has reconstituted its core group of human rights defenders and NGOs, according to an official notification.

Former BJP MLA and Padma Shri awardee Jitender Singh Shunty, director of Rights and Risk Analysis Group (RRAG) Suhas Chakma and former ambassador Bhaswati Mukherjee are part of the reconstituted 13-member team.

The core group has the job of identifying areas of cooperation between the NHRC and NGOs along with devising mechanisms for continuous and mean-

ingful interaction of the NHRC with the civil society, according to the terms of reference mentioned in the notification.

The notification also stated that the group will also review the outreach of the benefits of policies and welfare schemes and help in issuing advisories to fill gaps.

The Padma Shri awardee and his team were instrumental in ensuring dignity in death for COVID-19 patients during the second wave of the pandemic.

Shunty's non-profit organisation Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal has been cremating unclaimed bodies for over 25 years. **AGENCIES**

NHRC seeks timeline on fixing air quality

The National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Delhi government to fix a timeline to rectify the cause of poor air quality at hotspots and inquired about the status of alternative landfill sites. The NHRC on Friday held the third hearing of chief secretaries of Punjab, UP, Haryana and Delhi on air pollution in NCR in light of their reports. The next date of hearing has been fixed for November 25. PTI

Two jails to get latest jammers

FATEHGARH SAHIB, NOVEMBER 18

The government is going to introduce the latest jamming technology at two of the highly sensitive jails to control the use of mobile phones by inmates, said Harjot Bains, Minister for Jails and School Education, here today.

He had come to preside over the concluding ceremony of the state-level Teachers' Fest held at BBSB Engineering College, Fatehgarh Sahib.

Claiming that the government had brought a vast improvement in the condition of jails, Bains said officials had confiscated a large number of mobile phones and huge quantities of drugs from inmates.

He said this had been made possible by the strict action of the government. Several officials, including DSP, ASP, Superintendent, Senior Warden, Medical Officer and other employees, had been suspended for



Education Minister Harjot Bains at Teachers' Fest in Fatehgarh Sahib.

dereliction of duty, he said.

The minister said it would be for the first time in the history of Indian jails that, the latest jamming technology would be used whereas the jail inmates would enjoy all other facilities, which they were entitled to.

He said the government was contemplating setting up a state-of-the-art jail in one of the districts.

Answering a query regard-

ing an NHRC notice to the state government for lack of education facilities in border areas, he said it was unfortunate that some schools did not have proper infrastructure, including electricity supply. "We are making all efforts to improve education facilities and infrastructure not only in border areas, but all over the state," he said. — OC

Two jails to get latest jammers

FATEHGARH SAHIB, NOVEMBER 18

The government is going to introduce the latest jamming technology at two of the highly sensitive jails to control the use of mobile phones by inmates, said Harjot Bains, Minister for Jails and School Education, here today.

He had come to preside over the concluding ceremony of the state-level Teachers' Fest held at BBSB Engineering College, Fatehgarh Sahib.

Claiming that the government had brought a vast improvement in the condition of jails, Bains said officials had confiscated a large number of mobile phones and huge quantities of drugs from inmates.

He said this had been made possible by the strict action of the government. Several officials, including DSP, ASP, Superintendent, Senior Warden, Medical Officer and other employees, had been suspended for



Education Minister Harjot Bains at Teachers' Fest in Fatehgarh Sahib.

dereliction of duty, he said.

The minister said it would be for the first time in the history of Indian jails that, the latest jamming technology would be used whereas the jail inmates would enjoy all other facilities, which they were entitled to.

He said the government was contemplating setting up a state-of-the-art jail in one of the districts.

Answering a query regard-

ing an NHRC notice to the state government for lack of education facilities in border areas, he said it was unfortunate that some schools did not have proper infrastructure, including electricity supply. "We are making all efforts to improve education facilities and infrastructure not only in border areas, but all over the state," he said. — OC

एनएचआरसी ने कोर समूह गठित किया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने मानवाधिकारों और गैर सरकारी संगठनों का कोर समूह गठित किया है। एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गई। पुनर्गठित 13 सदस्यीय दल में पूर्व भाजपा विधायक तथा पद्मश्री सम्मान प्राप्त जितेंद्र सिंह शंटी, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) के निदेशक सुहास चकमा और पूर्व राजदूत बी मुखर्जी शामिल हैं।



एनएचआरसी ने कोर समूह गठित किया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने मानवाधिकारों और गैर सरकारी संगठनों का कोर समूह गठित किया है। एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गयी। पुनर्गठित 13 सदस्यीय दल में पूर्व भाजपा विधायक तथा पद्मश्री सम्मान प्राप्त जितेंद्र सिंह शंटी, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के निदेशक सुहास चकमा और पूर्व राजदूत बी मुखर्जी शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार कोर समूह का काम एनएचआरसी और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग के क्षेत्रों को चिह्नित करना तथा नागरिक समाज के साथ एनएचआरसी के सतत एवं सार्थक संवाद की प्रणालियां निर्धारित करना है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने को समयबद्ध योजना लागू करने के निर्देश

एनएचआरसी ने दिल्ली-एनसीआर के राज्यों के साथ की तीसरी बैठक

वायु प्रदूषण का मामला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निबटने और बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से कहा है कि वे रणनीतिक योजनाएं विकसित कर उन्हें समयबद्ध ढंग से लागू करें। आयोग ने राज्यों को ये निर्देश संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और अधिकारियों के साथ शुक्रवार को प्रदूषण के मुद्दे पर हुई तीसरी बैठक में राज्यों की ओर से दी गई रिपोर्ट देखने के बाद दिए। आयोग ने राज्यों से अगली सुनवाई 25 नवंबर पर इस संबंध में फिर रिपोर्ट मांगी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लोगों की जान के लिए खतरा और संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए संज्ञान लिया था। आयोग ने चारों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करके प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट भी मांगी थी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आयोग ने चारों राज्यों के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को

यूपी से मेडिकल वेस्ट व खतरनाक कचरे पर रिपोर्ट मांगी

आयोग ने यूपी से अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल और खतरनाक कचरे के निपटारे के संबंध में अलग से रिपोर्ट मांगी है। कितने अस्पतालों को इस संबंध में नोटिस दिया गया और कार्रवाई हुई। इसके साथ ही आयोग ने वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधा रोपण पर भी जोर दिया। आयोग ने राज्य सरकार से कहा कि फुटपाथ और सड़क के गड़बड़े भरने का काम पूरा करने के लिए मार्च 2023 की समय सीमा तय की जा सकती है। दिल्ली सरकार से आयोग ने कहा है कि वह वायु प्रदूषण के हाट स्पाट की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए एक

टाइम लाइन तय करे। इसके अलावा लैंडफिल की वैकल्पिक जगह तलाश जाने और कचरा निस्तारण की स्थिति भी दिल्ली से पूछी है। साथ ही दिल्ली में एनडीएमसी, परिवहन विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ग्रेप लागू करने के बारे में नोटिस जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, सीपीसीबी, डीडीए, डीएमआरसी, डीपीसीसी, एनएचएआई, सीपीडब्लूडी, एनबीसीसी से भी 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। इन्हें एनसीआर की हवा प्रदूषण मुक्त रखना सुनिश्चित करने के बारे में जवाब देना है।

पराली की घटनाओं का ब्योरा मांगा है। यह भी कहा कि अगर डीकंपोजर मशीन प्रभावी ढंग से काम नहीं की तो क्या विकल्प हो सकता है इसे भी राज्य तलाशे।

आयोग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सरकार से कहा है कि नगर निकायों के साथ समन्वय करके सभी शहरों की सफाई के लिए मैकेनाइज्ड सफाई मशीनें खरीदी जाएं और इसके लिए बजट में विशेष प्रविधान किए जाएं। राज्यों से कहा कि तय समय में चरणबद्ध ढंग से नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक रोडमैप होना चाहिए। बैठक के दौरान आयोग ने सैटिक टैंक, सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों पर चिंता जताई। आयोग ने कहा कि 24 सितंबर 2021 की एडवाइजरी लागू हो। जरूरी सुरक्षा उपकरण खरीदे जाएं। आयोग ने चेतावनी दी कि अधिकारी चेत जाएं नहीं तो आयोग क्रिमिनल कार्रवाई की संस्तुति करेगा। बैठक के दौरान आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अधिकारी यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उन्होंने सैटिक टैंक और सीवर की सफाई का काम ठेकेदार को दे दिया है। सरकार को जहरीली गैस के स्पाट चिन्हित कर वहां खतरे के सिग्नल लगाने चाहिए।

तीसरी बैठक की, जिसमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्यों द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा हुई। राज्यों ने आयोग को रिपोर्ट सौंपी जिसे देखने से पता चला कि राज्य सरकारों ने वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए पराली प्रबंधन, धूल और अस्पतालों और सीवर की गंदगी से निबटने के लिए कुछ काम किया है, लेकिन आयोग ने राज्यों से जोर देकर कहा कि वायु प्रदूषण और बेहतर नागरिक सुविधाएं देने के लिए

उन्हें रणनीतिक योजना विकसित करने की जरूरत है, जिसे समयबद्ध ढंग से लागू किया जाए। आयोग ने पंजाब सरकार से कहा कि उसे गरीब किसानों को पराली निस्तारण के लिए मशीनें मुहैया करानी चाहिए। आयोग ने पंजाब से कहा है कि वह रिपोर्ट में ब्योरा देगा कि राज्य में कितनी पराली निकलती है जिसमें से कितनी जलाई जाती है और कितनी प्रभावी ढंग से निस्तारित की जाती है। आयोग ने राज्य सरकार से स्थानवार

NHRC notice to T.N. chief secretary, DGP after four workers die while cleaning septic tank

<https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-notice-to-tn-chief-secretary-dgp-after-four-workers-die-while-cleaning-septic-tank/article66154322.ece>

The National Human Rights Commission on Friday issued notices to Tamil Nadu's chief secretary, DGP and a top civic body official after four workers were asphyxiated to death while cleaning a septic tank in Karur district. They have been given six weeks to respond, the NHRC said.

"The NHRC has taken suo motu cognizance of media reports that three workers were asphyxiated to death while cleaning a septic tank at an under-construction house in Gandhi Nagar area of Karur district on November 15.

"The Commission has issued notices to the chief secretary, Director General of Police and the municipal commissioner, Karur, calling for reports in the matter. They have been given six weeks to respond," the NHRC said in a statement.

The NHRC has asked the chief secretary to submit an action-taken report regarding the accountability of authorities who entrusted the job of cleaning the septic tank besides details of compensation and rehabilitation provided to the next of kin of the deceased, it said.

The NHRC said the report should also specify about awareness and sensitisation camps initiated by the State government to provide security cover to workers involved in cleaning of sewer or septic tanks as well as welfare schemes initiated or to be initiated for such sanitary workers.

"Action taken report must also contain implementation of the advisory issued by the NHRC on 24th September, 2021 about the protection of human rights of a person engaged in hazardous cleaning and its outcome," the NHRC said.

DGP asked to report status of FIR

The Director General of Police has been asked to report the status of the FIR filed in this connection.

The commission said the municipal commissioner has to submit a report specifying the public servant involved in the culpable negligence causing death by not enabling the workers to use safety gear and protective equipment while cleaning.

It should also specify the disciplinary action initiated against them as per the prevalent service rules, the panel said.

The commission also emphasised that in case of any sanitary or hazardous cleaning work, the local authority and the contractor or employers are to be held responsible and accountable jointly and severally irrespective of the type of hiring of the sanitary workers.

NHRC issues notice to TN govt over death of sanitation workers

<http://www.uniindia.com/nhrc-issues-notice-to-tn-govt-over-death-of-sanitation-workers/india/news/2863129.html>

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday said it issued notices to the Tamil Nadu government over reported death of three sanitation workers. Taking suo motu cognizance of media reports that three workers were asphyxiated to death while cleaning a septic tank at an underconstruction house in Gandhi Nagar area in Karur district on November 15, the Rights body said it issued notices to the state Chief Secretary, Director General of Police (DGP) and the Municipal Commissioner of Karur, calling for reports in the matter. They have been given six weeks to respond, the Commission said in a statement. The NHRC asked the CS to submit an action taken report regarding fixing the responsibility/accountability of the concerned authorities, who had entrusted the cleaning of the septic tank in the construction site, besides the details of compensation and rehabilitation provided to the next of kin of the deceased.

The report should also specify the awareness and sensitisation camps initiated by the state Government to provide security covers to workers involved in hazardous cleaning of sewer/septic tanks etc., as well as the welfare schemes initiated or to be initiated by it for such sanitary workers, as per the release. Action taken report must also contain implementation of the advisory issued by the NHRC on September 24 last year about the protection of human rights of the person engaged in hazardous cleaning and its outcome, it said. The DGP has been asked to report the status of the FIR filed in this connection, arrest, if any; whether contributory culpable negligence has been included in causing death, by invoking Section 304-A of IPC against the private or public persons, involved in engaging the deceased workers for cleaning of the septic tank in the under-construction house without safety gears, it added. The Municipal Commissioner has to submit a report specifying the public servants involved in the culpable negligence causing death by not enabling the workers to use safety gear and protective equipment while cleaning and the disciplinary action initiated against them as per the prevalent service rules, the Rights body said. The NHRC observed that in case of any sanitary work or hazardous cleaning work, the local authority and the contractor/employers are to be held responsible and accountable, jointly and severally irrespective of the type of hiring/engagement of the sanitary workers.

Press Trust of India/Nyooz/ The Print/ The Week

NHRC notice to TN chief secy, DGP after 3 workers die due to

<https://www.ptinews.com/news/national/nhrc-notice-to-tn-chief-secy-dgp-after-3-workers-die-due-to-asphyxiation-while-cleaning-septic-tank/2/460959.html>

<https://www.nyooz.com/news/delhi/1705670/nhrc-notice-to-tn-chief-secy-dgp-after-3-workers-die-due-to-asphyxiation-while-cleaning-septic-tank/>

<https://theprint.in/india/nhrc-notice-to-tn-chief-secy-dgp-after-3-workers-die-due-to-asphyxiation-while-cleaning-septic-tank/1224041/>

<https://www.theweek.in/wire-updates/national/2022/11/18/des57-dl-nhrc-tn-notices.html>

The National Human Rights Commission on Friday issued notices to Tamil Nadu's chief secretary, DGP and a top civic body official after three workers were asphyxiated to death while cleaning a septic tank in Karur district.

They have been given six weeks to respond, the NHRC said.

"The NHRC has taken suo motu cognizance of media reports that three workers were asphyxiated to death while cleaning a septic tank at an under-construction house in Gandhi Nagar area of Karur district on November 15.

"The Commission has issued notices to the chief secretary, Director General of Police and the municipal commissioner, Karur, calling for reports in the matter. They have been given six weeks to respond," the NHRC said in a statement.

The NHRC has asked the chief secretary to submit an action-taken report regarding fixing of accountability of authorities who entrusted the job of cleaning the septic tank besides details of compensation and rehabilitation provided to the next of kin of the deceased, it said.

The NHRC said the report should also specify about awareness and sensitization camps initiated by the state government to provide security cover to workers involved in cleaning of sewer or septic tanks as well as welfare schemes initiated or to be initiated for such sanitary workers.

"Action taken report must also contain implementation of the advisory issued by the NHRC on 24th September, 2021 about the protection of human rights of a person engaged in hazardous cleaning and its outcome," the NHRC said.

The Director General of Police has been asked to report the status of the FIR filed in this connection.

The commission said the municipal commissioner has to submit a report specifying the public servant involved in the culpable negligence causing death by not enabling the workers to use safety gear and protective equipment while cleaning.

It should also specify the disciplinary action initiated against them as per the prevalent service rules, the panel said.

The commission also emphasised that in case of any sanitary or hazardous cleaning work, the local authority and the contractor or employers are to be held responsible and accountable jointly and severally irrespective of the type of hiring of the sanitary workers. PTI VA TDS

TDS

ANI News/ Devdiscourse

NHRC issues notice to Tamil Nadu govt over death of 3 ...

<https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-issues-notice-to-tamil-nadu-govt-over-death-of-3-sanitation-workers20221118164012>

<https://www.devdiscourse.com/article/headlines/2256683-nhrc-issues-notice-to-tamil-nadu-govt-over-death-of-3-sanitation-workers>

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday said it issued notice to the Tamil Nadu government over the reported death of three sanitation workers during cleaning of a septic tank. Taking suo motu cognizance of media reports that three workers were asphyxiated to death while cleaning a septic tank at an under-construction house in the Gandhi Nagar area in Karur district on November 15, the Commission issued notices to the State Chief Secretary, Director General of Police (DGP) and the Municipal Commissioner of Karur, calling for reports in the matter. The Commission said they had been given six weeks to respond. The NHRC asked the Chief Secretary to submit an action-taken report regarding fixing the responsibility or accountability of the authorities concerned, who had entrusted the cleaning of the septic tank in the construction site, besides the details of compensation and rehabilitation provided to the next of kin of the deceased. "The report should also specify the awareness and sensitization camps initiated by the State Government to provide security covers to workers involved in hazardous cleaning of sewer/septic tanks etc., as well as the welfare schemes initiated or to be initiated by the State Government for such sanitary workers. Action taken report must also contain implementation of the Advisory issued by the NHRC on September 24, 2021, about the protection of human rights of the person engaged in hazardous cleaning and its outcome," the commission said. The DGP has been asked to report the status of the FIR filed in this connection, arrest, if any; whether contributory culpable negligence has been included in causing death, by invoking Section 304-A IPC against the private or public persons, involved in engaging the deceased workers for cleaning of the septic tank in the under-construction house without safety gears. The Municipal Commissioner has to submit a report specifying the public servant(s) involved in the culpable negligence causing death by not enabling the workers to use safety gear and protective equipment while cleaning and the disciplinary action initiated against them as per the prevalent service rules. "Issuing the notices, the Commission has observed that in spite of its Advisory, the Supreme Court Judgment in Safai Karamchari Andolan Ors. Vs. Union of India and Others (WP(C) No.583 of 2003) on March 27, 2014, providing for the specific mandate to the local authorities and other agencies to use modern technology for cleaning, and enactment of the "Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013", the incidents of death of sanitary workers while entering/cleaning septic tank/sewer lines, have been happening unabated," it said. The Paramount consideration of the Commission is to ensure the complete eradication and abolition of sewage cleaning by sanitary workers manually, which runs completely contrary to the concept of the abolition of untouchability, as envisaged, in Article 17 of the Constitution of India. It also emphasized that in case of any sanitary work or hazardous cleaning work, the local authority and the contractor/employers are to be held responsible and accountable,

jointly and severally irrespective of the type of hiring/engagement of the sanitary workers. (ANI)

NHRC issues notice to Tamil Nadu govt after 3 die cleaning ...

<https://www.hindustantimes.com/india-news/nhrc-issues-notice-to-tamil-nadu-govt-after-3-die-cleaning-septic-tank-101668782678650-amp.html>

Three people died on Tuesday while cleaning a septic tank at an under-construction house in the Gandhi Nagar area of the Karur district in Tamil Nadu, according to National Human Rights Commission (NHRC).

The Commission, while taking suo moto cognizance of the matter came down heavily on the Tamil Nadu government over the death of the workers due to manual scavenging.

It observed that despite the Supreme Court's judgment, which provided a specific mandate to the local authorities and other agencies to use modern technology for cleaning, and enactment of the "Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013" - the number of casualties have been rampant.

Also Read: Shortage of essential medicines in Navi Mumbai

NHRC further issued notices to the chief secretary, director general of police, Tamil Nadu, and the municipal commissioner and asked them to submit a report within six weeks of the case.

As Rahul steps up attack on Savarkar, govt demands apology; Uddhav questions BJP-RSS's contribution to freedom struggle

'Cong leaked caste-census report for political gains': Karnataka health minister

In a statement, NHRC said, "The chief secretary has to submit an action taken report regarding fixing the responsibility/accountability of the concerned authorities, who had entrusted the cleaning of the septic tank at the construction site."

The report by the NHRC also asked the senior bureaucrat about the compensations, if any, that had been provided to the next of kin of the deceased. The report further asked to update on the welfare schemes that provide security covers to sanitary workers contributing to high-risk jobs that had been initiated or were to be initiated by the state government.

"Action taken report must also contain implementation of the advisory issued by the NHRC on 24th September 2021 about the protection of human rights of the person engaged in hazardous cleaning and its outcome," the NHRC said in the release.

Additionally, the DGP has been requested to submit the FIR of the incident and if someone was apprehended due to negligence in the case.

NHRC also asked the municipal commissioner to act on the case. "Municipal commissioner Karur has to submit a report specifying the public servant(s) involved in the culpable negligence causing death by not enabling the workers to use safety gear and protective equipment while cleaning and the disciplinary action initiated against them as per the prevalent service rules," the NHRC mentioned in the release.

According to the Centre's data, over 941 casualties were reported due to the cleaning of sewers and septic tanks. Tamil Nadu contributed to the highest number of deaths at 213, with Gujarat taking the second spot at 152 and UP and Delhi at 104 and 98 respectively.

This data was collected by 21 state governments, as informed by the Centre based on surveys conducted by local authorities in 2013 and 2018.

The survey noted that 58,098 people were working as manual scavengers.

NHRC notice to Tamil Nadu chief secy, DGP after 3 workers ...

<https://indianexpress.com/article/cities/chennai/tamil-nadu-karur-septic-tank-cleaning-asphyxiation-death-nhrc-8276692/lite/>

The National Human Rights Commission on Friday issued notices to Tamil Nadu's chief secretary, DGP and a top civic body official after three workers were asphyxiated to death while cleaning a septic tank in Karur district.

They have been given six weeks to respond, the NHRC said.

"The NHRC has taken suo motu cognizance of media reports that three workers were asphyxiated to death while cleaning a septic tank at an under-construction house in Gandhi Nagar area of Karur district on November 15.

Read also |Strive to make Tamil Nadu the best in industrial development: CM MK Stalin

"The Commission has issued notices to the chief secretary, Director General of Police and the municipal commissioner, Karur, calling for reports in the matter. They have been given six weeks to respond," the NHRC said in a statement.

The NHRC has asked the chief secretary to submit an action-taken report regarding fixing of accountability of authorities who entrusted the job of cleaning the septic tank besides details of compensation and rehabilitation provided to the next of kin of the deceased, it said.

The NHRC said the report should also specify about awareness and sensitization camps initiated by the state government to provide security cover to workers involved in cleaning of sewer or septic tanks as well as welfare schemes initiated or to be initiated for such sanitary workers.

"Action taken report must also contain implementation of the advisory issued by the NHRC on 24th September, 2021 about the protection of human rights of a person engaged in hazardous cleaning and its outcome," the NHRC said.

The Director General of Police has been asked to report the status of the FIR filed in this connection.

The commission said the municipal commissioner has to submit a report specifying the public servant involved in the culpable negligence causing death by not enabling the workers to use safety gear and protective equipment while cleaning.

It should also specify the disciplinary action initiated against them as per the prevalent service rules, the panel said.

NHRC issues notice to Punjab govt over poor access to educational facilities in Kaluwara

<https://www.financialexpress.com/education-2/nhrc-issues-notice-to-punjab-govt-over-poor-access-to-educational-facilities-in-kaluwara/2838567/>

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Punjab government over a media report which claimed that students in Kaluwara village of the state do not have access to proper educational facilities.

The commission took suo motu cognizance of the media report. As per an official statement, students, especially the girls in Kaluwara village, first walk on foot in slushy banks of the river Sutlej, then board a 'berhi' (wooden boat) and cross the river to walk for another 4 kms along the border with Pakistan before finally reaching the Government Senior Secondary School in Gatti Rajoke area of Ferozpur district.

"The media report further revealed that Kaluwara is surrounded on three sides by river water and by the border fence on the fourth. During heavy rain, the river floods fields and homes, forcing the residents to spend days on roof tops. The village houses 50 families and has only one primary school. Most of the girls studying in the primary school drop out after class five," the NHRC statement said.

UP recommends CBI probe into irregularities in admission to AYUSH colleges in 2021
The Commission has also sought a report from the Punjab government and asked it to mention what steps have been taken or proposed to provide better and hassle-free access to students in the area, either by building a new school at a nearby place or by providing better commuting facilities.

"The Commission has observed that it becomes imperative that the state government makes it possible for every child to get an access to the education system, without much hindrance or difficulty so that the fundamental significance of the life of an individual can be achieved," the statement added.

Give free tools to farmers to prevent stubble burning: NHRC

<https://theprint.in/india/give-free-tools-to-farmers-to-prevent-stubble-burning-nhrc/1224466/>

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday held a third round of meeting through video conferencing with the Chief Secretaries of Delhi, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh and asked them to give a detailed report on how to prevent air pollution in the Delhi-NCR region.

The meeting was held with Chief Secretaries of four states through video conferencing under the chairmanship of NHRC Chairman Justice Arun Kumar Mishra regarding air pollution as the national capital and the NCR region continues to be covered with a heavy blanket of smog.

In the last hearing, the Chief Secretaries of Punjab, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh were summoned to control air pollution in Delhi NCR.

In today's meeting, all the secretaries, while sharing the report, presented many more facts on the same issues. Now the next hearing has been fixed on 25 November.

While speaking to ANI, NHRC spokesperson Jaimini Kumar Srivastava said that a detailed discussion was held on stubble burning which is one of the biggest reasons for the bad air quality.

"The Commission had a discussion on how to provide the equipment to the poor farmers at the panchayat and body level free of cost so that they can harvest the paddy properly on time. Those who have the capacity to buy equipment should be made available at low cost so that farmers are not forced to burn stubble," he said.

Srivastava further said that apart from this, the Commission also asked the governments to provide proper equipment to the sanitation workers of the states.

"Be it the waste of hospitals or the dust on the roads, due to which air pollution increases, it should be managed. The Commission has asked for the details of how many mechanized devices are there to cope with the pollution caused by stubble burning and in what capacity they are being ordered. In many states of the country, various topics like pollution caused by stubble burning and deaths of sanitation workers, etc. were discussed with the Chief Secretaries of the states and instructions were also given to prevent and reduce pollution," NHRC spokesperson said.

In the last hearing, the Commission reprimanded the governments of four states, Punjab, Haryana, Delhi, and Uttar Pradesh holding them responsible for poor management of 'stubble burning' after hearing the version of the Chief Secretaries of the respective states.

NHRC heard the Chief Secretaries of Delhi, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh on Thursday in connection with its suo motu cognizance of unabated air pollution in Delhi-

NCR as reported in media. "The Commission, after considering the responses of the concerned States and the Government of NCT of Delhi, and the deliberations thereon is of the opinion that the farmers are burning stubble under compulsion," NHRC said in a press release.

Delivering the judgement, the National Human Rights Commission noted that the governments of the states mentioned above failed to obviate the recurring problem of stubble burning, which led to the deterioration of air quality.

"The State Governments have to provide harvest machines to get rid of those stubbles but they have failed to provide an adequate number of requisite machines and other measures, as a result, farmers were forced to burn the stubbles, causing pollution," the commission said, adding that none of the States can blame the farmers for stubble burning, instead, it is due to the failure of all four State Governments that the stubble burning is happening in the four States causing enormous pollutants in the air. (ANI)

Give Free Tools To Farmers To Prevent Stubble Burning: Human Rights Body

<https://www.ndtv.com/india-news/give-free-tools-to-farmers-to-prevent-stubble-burning-human-rights-body-3534290>

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday held a third round of meeting through video conferencing with the Chief Secretaries of Delhi, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh and asked them to give a detailed report on how to prevent air pollution in the Delhi-NCR region.

The meeting was held with Chief Secretaries of four states through video conferencing under the chairmanship of NHRC Chairman Justice Arun Kumar Mishra regarding air pollution as the national capital and the NCR region continues to be covered with a heavy blanket of smog.

In the last hearing, the Chief Secretaries of Punjab, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh were summoned to control air pollution in Delhi NCR.

In today's meeting, all the secretaries, while sharing the report, presented many more facts on the same issues. Now the next hearing has been fixed on 25 November.

While speaking to ANI, NHRC spokesperson Jaimini Kumar Srivastava said that a detailed discussion was held on stubble burning which is one of the biggest reasons for the bad air quality.

"The Commission had a discussion on how to provide the equipment to the poor farmers at the panchayat and body level free of cost so that they can harvest the paddy properly on time. Those who have the capacity to buy equipment should be made available at low cost so that farmers are not forced to burn stubble," he said.

Srivastava further said that apart from this, the Commission also asked the governments to provide proper equipment to the sanitation workers of the states.

"Be it the waste of hospitals or the dust on the roads, due to which air pollution increases, it should be managed. The Commission has asked for the details of how many mechanized devices are there to cope with the pollution caused by stubble burning and in what capacity they are being ordered. In many states of the country, various topics like pollution caused by stubble burning and deaths of sanitation workers, etc. were discussed with the Chief Secretaries of the states and instructions were also given to prevent and reduce pollution," NHRC spokesperson said.

In the last hearing, the Commission reprimanded the governments of four states, Punjab, Haryana, Delhi, and Uttar Pradesh holding them responsible for poor management of 'stubble burning' after hearing the version of the Chief Secretaries of the respective states.

NHRC heard the Chief Secretaries of Delhi, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh on Thursday in connection with its suo motu cognizance of unabated air pollution in Delhi-

NCR as reported in media. "The Commission, after considering the responses of the concerned States and the Government of NCT of Delhi, and the deliberations thereon is of the opinion that the farmers are burning stubble under compulsion," NHRC said in a press release.

Delivering the judgement, the National Human Rights Commission noted that the governments of the states mentioned above failed to obviate the recurring problem of stubble burning, which led to the deterioration of air quality.

"The State Governments have to provide harvest machines to get rid of those stubbles but they have failed to provide an adequate number of requisite machines and other measures, as a result, farmers were forced to burn the stubbles, causing pollution," the commission said, adding that none of the States can blame the farmers for stubble burning, instead, it is due to the failure of all four State Governments that the stubble burning is happening in the four States causing enormous pollutants in the air.



एनएचआरसी का कोर समूह गठित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने मानवाधिकारों और गैर सरकारी संगठनों का कोर समूह गठित किया है। एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गई।

पुनर्गठित 13 सदस्यीय दल में पूर्व भाजपा विधायक तथा पद्मश्री सम्मान प्राप्त जितेंद्र सिंह शंटी, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के निदेशक सुहास चकमा और पूर्व राजदूत बी मुखर्जी शामिल हैं।

NHRC reconstitutes core group of human rights defenders, NGOs

<https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-reconstitutes-core-group-of-human-rights-defenders-ngos/article66153344.ece>

The National Human Rights Commission (NHRC) has reconstituted its core group of human rights defenders and NGOs, an official notification said.

Former BJP MLA and Padma Shri awardee Jitender Singh Shunty, Suhas Chakma, director of Rights and Risk Analysis Group (RRAG), and former ambassador Bhaswati Mukherjee are part of the reconstituted 13-member team.

The core group has the job of identifying areas of cooperation between the NHRC and NGOs along with devising mechanisms for continuous and meaningful interaction of the NHRC with the civil society, according to the terms of reference mentioned in the notification.

The notification also mentioned that the group will also review the outreach of the benefits of policies and welfare schemes and help in issuing advisories to fill gaps.

NHRC reforms core group of human rights defenders

<https://arunachaltimes.in/index.php/2022/11/19/nhrc-reforms-core-group-of-human-rights-defenders/>

The National Human Rights Commission (NHRC) has reconstituted its core group of human rights defenders and NGOs, according to an official notification.

Former BJP MLA Jitender Singh Shunty, Rights and Risk Analysis Group (RRAG) director Suhas Chakma, and former ambassador Bhaswati Mukherjee are part of the reconstituted 13-member team.

The core group has the job of identifying areas of cooperation between the NHRC and NGOs, along with devising mechanisms for continuous and meaningful interaction of the NHRC with the civil society, according to the terms of reference mentioned in the notification.

The notification also stated that the group will also review the outreach of the benefits of policies and welfare schemes and help in issuing advisories to fill gaps. Shunty and his team were instrumental in ensuring dignity in death for Covid-19 patients during the second wave of the pandemic. (PTI)



एनएचआरसी का कोर समूह गठित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने मानवाधिकारों और गैर सरकारी संगठनों का कोर समूह गठित किया है। एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गई।

पुनर्गठित 13 सदस्यीय दल में पूर्व भाजपा विधायक तथा पद्मश्री सम्मान प्राप्त जितेंद्र सिंह शंटी, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के निदेशक सुहास चकमा और पूर्व राजदूत बी मुखर्जी शामिल हैं।

NHRC reconstitutes core group of human rights defenders ...

<http://www.millenniumpost.in/nation/nhrc-reconstitutes-core-group-of-human-rights-defenders-ngos-499548>

The National Human Rights Commission (NHRC) has reconstituted its core group of human rights defenders and NGOs, according to an official notification. Former BJP MLA and Padma Shri awardee Jitender Singh Shunty, director of Rights and Risk Analysis Group (RRAG) Suhas Chakma and former ambassador Bhaswati Mukherjee are part of the reconstituted 13-member team. The core group has the job of identifying areas of cooperation between the NHRC and NGOs along with devising mechanisms for continuous and meaningful interaction of the NHRC with the civil society, according to the terms of reference mentioned in the notification. The notification also stated that the group will also review the outreach of the benefits of policies and welfare schemes and help in issuing advisories to fill gaps. The Padma Shri awardee and his team were instrumental in ensuring dignity in death for COVID-19 patients during the second wave of the pandemic. Shunty's non-profit organisation Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal has been cremating unclaimed bodies for over 25 years.

NHRC reconstitutes core group of human rights defenders NGOs

<https://www.tribuneindia.com/news/nation/nhrc-reconstitutes-core-group-of-human-rights-defenders-ngos-452230>

The National Human Rights Commission (NHRC) has reconstituted its core group of human rights defenders and NGOs, according to an official notification.

Former BJP MLA and Padma Shri awardee Jitender Singh Shunty, director of Rights and Risk Analysis Group (RRAG) Suhas Chakma and former ambassador Bhaswati Mukherjee are part of the reconstituted 13-member team.

The core group has the job of identifying areas of cooperation between the NHRC and NGOs along with devising mechanisms for continuous and meaningful interaction of the NHRC with the civil society, according to the terms of reference mentioned in the notification.

The notification also stated that the group will also review the outreach of the benefits of policies and welfare schemes and help in issuing advisories to fill gaps.

The Padma Shri awardee and his team were instrumental in ensuring dignity in death for COVID-19 patients during the second wave of the pandemic.

Shunty's non-profit organisation Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal (SBSSD) has been cremating unclaimed bodies for over 25 years.

However, the second wave of the coronavirus pandemic was especially busy for SBSSD as bodies piled up in hospital mortuaries amid the pandemic.

National Human Rights Body Reconstitutes 13 Member Core Team, NGOs

<https://www.ndtv.com/india-news/national-human-rights-body-reconstitutes-13-member-core-team-ngos-3533077>

The National Human Rights Commission (NHRC) has reconstituted its core group of human rights defenders and NGOs, according to an official notification.

Former BJP MLA and Padma Shri awardee Jitender Singh Shunty, director of Rights and Risk Analysis Group (RRAG) Suhas Chakma and former ambassador Bhaswati Mukherjee are part of the reconstituted 13-member team.

The core group has the job of identifying areas of cooperation between the NHRC and NGOs along with devising mechanisms for continuous and meaningful interaction of the NHRC with the civil society, according to the terms of reference mentioned in the notification.

The notification also stated that the group will also review the outreach of the benefits of policies and welfare schemes and help in issuing advisories to fill gaps.

The Padma Shri awardee and his team were instrumental in ensuring dignity in death for COVID-19 patients during the second wave of the pandemic.

Mr Shunty's non-profit organisation Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal (SBSSD) has been cremating unclaimed bodies for over 25 years.

However, the second wave of the coronavirus pandemic was especially busy for SBSSD as bodies piled up in hospital mortuaries amid the pandemic.

NHRC reconstitutes core group of human rights defenders , NGOs

<https://www.dailypioneer.com/2022/top-stories/nhrc-reconstitutes-core-group-of-human-rights-defenders--ngos.html>

NHRC reconstitutes core group of human rights defenders, NGOs

The National Human Rights Commission (NHRC) has reconstituted its core group of human rights defenders and NGOs, an official notification said.

Former BJP MLA and Padma Shri awardee Jitender Singh Shunty, Suhas Chakma, director of Rights and Risk Analysis Group (RRAG), and former ambassador Bhaswati Mukherjee are part of the reconstituted 13-member team.

The core group has the job of identifying areas of cooperation between the NHRC and NGOs along with devising mechanisms for continuous and meaningful interaction of the NHRC with the civil society, according to the terms of reference mentioned in the notification.

The notification also mentioned that the group will also review the outreach of the benefits of policies and welfare schemes and help in issuing advisories to fill gaps.

Press Trust of India/ The Week/ ThePrint

NHRC reconstitutes core group of human rights defenders ...

<https://www.ptinews.com/news/north/nhrc-reconstitutes-core-group-of-human-rights-defenders-ngos/460784.html>

<https://www.theweek.in/wire-updates/national/2022/11/18/des33-nhrc-ld-core-group.html>

<https://theprint.in/india/nhrc-reconstitutes-core-group-of-human-rights-defenders-ngos/1223725/>

The National Human Rights Commission (NHRC) has reconstituted its core group of human rights defenders and NGOs, an official notification said. Former BJP MLA and Padma Shri awardee Jitender Singh Shunty, Suhas Chakma, director of Rights and Risk Analysis Group (RRAG), and former ambassador Bhaswati Mukherjee are part of the reconstituted 13-member team. The core group has the job of identifying areas of cooperation between the NHRC and NGOs along with devising mechanisms for continuous and meaningful interaction of the NHRC with the civil society, according to the terms of reference mentioned in the notification.

NHRC holds 3rd hearing of states regarding air pollution

<https://theprint.in/india/nhrc-holds-3rd-hearing-of-states-regarding-air-pollution/1224532/>

The National Human Rights Commission India on Friday held the 3rd hearing of the Chief Secretaries of Punjab, Uttar Pradesh, Haryana and Delhi in the matter of air pollution in Delhi NCR in the light of the reports submitted by them in response to its directions in the last meeting.

Seeking further reports, the next date of hearing has been fixed for November 25, 2022.

While noting some of the actions taken by the State governments with regard to controlling air pollution by managing stubble, dust, the hospital in sewage waste, among others, the Commission emphasized that they needed to have a strategic plan in place to plug the gaps between the policies and implementation thereof for providing clean air and atmosphere with better civic amenities ensuring the protection of the right to life and health of the citizens.

The Commission said that, "Government of Punjab will have to have dedicated machines for poor farmers for harvesting and disposal of stubble. The machines should be procured and provided to the poor farmers through the panchayats or cooperatives free of cost for harvesting to bring down the incidents of stubble burning to zero. Some fees may be charged from those who could afford it."

The Commission asked for the specific details of stubble generated; how much was burnt and how much was processed effectively by specifying place-wise incidents. It also asked to find out the alternatives, if crop residue decomposer machines are not effectively working.

It was stated that the States need to purchase mechanized sweeping machines for every city in coordination with the civic bodies and make special provisions in the budget for the same. There should be a road map for providing civic amenities in a phased but time-bound manner.

The Commission was particularly concerned about the deaths of persons involved in hazardous cleaning without protective gear and asked that the governments should implement the NHRC Advisory of September 2021, invigorate the local bodies and purchase mechanical cleaning devices like Bandicoots and safety equipment for those involved in such hazardous cleaning in septic tanks. The Commission said it is high time that the public functionaries take note of it otherwise it will be constrained to recommend criminal proceedings against them.

"The Commission further said, "the officials cannot absolve themselves of their statutory responsibilities by diverting these to a contractor for cleaning septic tanks and sewage. It also said that government should identify the spots, where there is a danger of poisonous gas and install danger signals."

A specific report has been called from the Government of Uttar Pradesh about the number of hospitals served notice for not complying with the guidelines for disposal of medical waste and the date-wise details of the action taken for revocation of the licenses of those flouting the norms.

It emphasized that tree plantation and their survival has to be monitored regularly to ensure green belt cover and clean air. A time frame of March, 2023 may fix to complete the work of unpaved roads and potholes.

The Commission asked the Delhi government to fix a timeline to find out and rectify the cause of poor air quality at the hot spots and when these will become normal. The Commission also enquired about the status of alternative landfill sites for garbage disposal and cleaning thereof.

In the meanwhile notices are also being issued to the concerned heads of NDMC, Transport Department, Delhi Jail Board, Police Department, Commission for Air Quality, GRAP, Delhi Cantonment Board, CPWD, NBCC, NHAI, DMRC, Central Pollution Control Board, DDA and NCDRC, Delhi Pollution Control Board for submitting their response before November 25 in connection with steps being taken or proposed to be taken to improve air quality in Delhi NCR to ensure safe health and ambient atmosphere for the citizens. (ANI)

Fix timeline to rectify cause of poor AQI at hotspots: NHRC ...

https://www.business-standard.com/article/current-affairs/fix-timeline-to-rectify-cause-of-poor-aqi-at-hotspots-nhrc-asks-delhi-govt-122111801168_1.html

The National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Delhi government to fix a timeline to rectify the cause of poor air quality at hotspots and inquired about the status of alternative landfill sites.

The NHRC on Friday held the third hearing of chief secretaries of Punjab, Uttar Pradesh, Haryana and Delhi on air pollution in Delhi NCR in light of reports submitted by them in response to its directions in the last meeting. Seeking further reports, the next date of hearing has been fixed for November 25.

"The commission asked the Delhi government to fix a timeline to find out and rectify the cause of poor air quality at the hot spots and when these will become normal. The commission also enquired about the status of alternative landfill sites for garbage disposal and cleaning thereof," it said in a statement.

While taking note of some of the actions taken by the state governments to control air pollution by managing stubble, dust, and hospital sewage, among others, the panel emphasised that they needed a strategic plan to plug the gap between policy and implementation.

The panel said the Punjab government would need to have dedicated machines for poor farmers to harvest and dispose of stubble. These machines should be procured and provided free of cost to the poor farmers through panchayats or cooperatives to bring down incidents of stubble burning to zero.

It asked for specific details of stubble generated, how much was burnt and how much was processed effectively by specifying place-wise incidents. It also asked the government to find alternatives if crop residue decomposer machines were not effective.

The states need to purchase mechanised sweeping machines for every city in coordination with civic bodies and make special provisions in the budget, it said.

There should be a roadmap to provide civic amenities in a phased but time-bound manner, the panel added.

It also expressed concern over the deaths of persons involved in "hazardous cleaning" without protective gear. It asked the governments to purchase mechanical cleaning devices such as 'bandicoots' and safety equipment for those involved in such "hazardous cleaning" in septic tanks.

The human rights body said it was high time that public functionaries took note of the hazard, failing which it would be constrained to recommend criminal proceedings against them, according to the statement.

The panel said officials could not absolve themselves of their statutory responsibilities by diverting the cleaning of septic tanks and sewage to a contractor. It also said the government should identify the spots where there was a danger of poisonous gas and install danger signals.

It has also asked for a specific report from the Uttar Pradesh government on the number of hospitals served notices for not complying with the guidelines for disposal of medical waste and the date-wise details of action taken for revocation of the licences of those facilities found flouting the norms.

The panel is also issuing notices to the Delhi government's Transport and Police departments, Delhi Jal Board, Commission for Air Quality Management, Delhi Cantonment Board, Central Public Works Department, NBCC India, National Highways Authority of India, Delhi Metro Rail Corporation, Central Pollution Control Board, Delhi Development Authority and Delhi Pollution Control Board to submit their responses before November 25 in connection with the steps being taken or proposed to improve air quality in Delhi-NCR to ensure safe health and ambient atmosphere for citizens, it said.

NHRC asks Delhi government to fix timeline to rectify cause of ...

<https://economictimes.indiatimes.com/news/india/nhrc-asks-delhi-government-to-fix-timeline-to-rectify-cause-of-poor-air-quality-at-hotspots/articleshow/95611234.cms>

The National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Delhi government to fix a timeline to rectify the cause of poor air quality at hotspots and inquired about the status of alternative landfill sites. The NHRC on Friday held the third hearing of chief secretaries of Punjab, Uttar Pradesh, Haryana and Delhi on air pollution in Delhi NCR in light of reports submitted by them in response to its directions in the last meeting. Seeking further reports, the next date of hearing has been fixed for November 25. "The commission asked the Delhi government to fix a timeline to find out and rectify the cause of poor air quality at the hot spots and when these will become normal. The commission also enquired about the status of alternative landfill sites for garbage disposal and cleaning thereof," it said in a statement. While taking note of some of the actions taken by the state governments to control air pollution by managing stubble, dust, and hospital sewage, among others, the panel emphasised that they needed a strategic plan to plug the gap between policy and implementation.

The panel said the Punjab government would need to have dedicated machines for poor farmers to harvest and dispose of stubble. These machines should be procured and provided free of cost to the poor farmers through panchayats or cooperatives to bring down incidents of stubble burning to zero. It asked for specific details of stubble generated, how much was burnt and how much was processed effectively by specifying place-wise incidents. It also asked the government to find alternatives if crop residue decomposer machines were not effective. The states need to purchase mechanised sweeping machines for every city in coordination with civic bodies and make special provisions in the budget, it said. There should be a roadmap to provide civic amenities in a phased but time-bound manner, the panel added. It also expressed concern over the deaths of persons involved in "hazardous cleaning" without protective gear. It asked the governments to purchase mechanical cleaning devices such as 'bandicoots' and safety equipment for those involved in such "hazardous cleaning" in septic tanks.

The human rights body said it was high time that public functionaries took note of the hazard, failing which it would be constrained to recommend criminal proceedings against them, according to the statement. The panel said officials could not absolve themselves of their statutory responsibilities by diverting the cleaning of septic tanks and sewage to a contractor. It also said the government should identify the spots where there was a danger of poisonous gas and install danger signals

It has also asked for a specific report from the Uttar Pradesh government on the number of hospitals served notices for not complying with the guidelines for disposal of medical waste and the date-wise details of action taken for revocation of the licences of those facilities found flouting the norms. The panel is also issuing notices to the Delhi government's Transport and Police departments, Delhi Jal Board, Commission for Air Quality Management, Delhi Cantonment Board, Central Public Works Department, NBCC India, National Highways Authority of India, Delhi Metro Rail Corporation, Central

Pollution Control Board, Delhi Development Authority and Delhi Pollution Control Board to submit their responses before November 25 in connection with the steps being taken or proposed to improve air quality in Delhi-NCR to ensure safe health and ambient atmosphere for citizens, it said.

NHRC holds hearing over air pollution in Delhi-NCR

<http://www.uniindia.com/news/india/nhrc-holds-hearing-over-air-pollution-in-delhi-ncr/2863656.html>

) The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday held the third hearing of the Chief Secretaries of Punjab, Uttar Pradesh, Haryana and Delhi in the matter of air pollution in Delhi-NCR in the light of the reports submitted by them in response to its directions in the last meeting. Seeking further reports, the next date of hearing has been fixed for November 25, the Rights body said in a statement. While noting some of the actions taken by the State governments with regard to controlling air pollution by managing stubble, dust, the hospital in sewage waste, among others, the Commission emphasised that they needed to have a strategic plan in place to plug the gaps between the policies and implementation thereof for providing clean air and atmosphere with better civic amenities ensuring the protection of the right to life and health of the citizens. The Commission said that the Punjab government will have to have dedicated machines for poor farmers for harvesting and disposal of stubble. The machines should be procured and provided to the poor farmers through the panchayats or cooperatives free of cost for harvesting to bring down the incidents of stubble burning to zero. Some fees may be charged from those who could afford it.

The NHRC asked for the specific details of stubble generated, how much was burnt and how much was processed effectively by specifying place-wise incidents. It also asked to find out the alternatives, if crop residue decomposer machines are not effectively working. The Commission was particularly concerned about the deaths of persons involved in hazardous cleaning without protective gear and asked that the governments should implement the NHRC advisory of September 24 last year, invigorate the local bodies and purchase mechanical cleaning devices like bandicoots and safety equipment for those involved in such hazardous cleaning in septic tanks. It is high time that the public functionaries take note of it otherwise it will be constrained to recommend criminal proceedings against them, the NHRC observed. It also said that government should identify the spots, where there is a danger of poisonous gas and install danger signals. A specific report has been called from the Uttar Pradesh government about the number of hospitals served notice for not complying with the guidelines for disposal of medical waste and the date-wise details of the action taken for revocation of the licenses of those flouting the norms, the Commission said. The NHRC asked the Delhi government to fix a timeline to find out and rectify the cause of poor air quality at the hot spots and when these will become normal.

NHRC: मानवाधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों के कोर ग्रुप का पुनर्गठन, ये होगा काम

<https://www.amarujala.com/india-news/nhrc-reconstitutes-core-group-of-human-rights-defenders-ngos>

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं (ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स) और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का एक कोर ग्रुप पुनर्गठित किया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

भाजपा के पूर्व विधायक और पद्म श्री पुरस्कार विजेता जितेंद्र सिंह शंटी, आरआरएजी (रिस्क एनालिसिस ग्रुप) के निदेशक सुहास चकमा और पूर्व राजदूत भसवती मुखर्जी भी इस 13 सदस्यीय पुनर्गठित टीम का हिस्सा हैं।

अधिसूचना में जिन शर्तों का जिक्र किया गया है, उनके मुताबिक इस कोर ग्रुप का काम एनएचआरसी और एनजीओ के बीच सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना है। इसके अलावा एनएचआरसी की नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) के साथ निरंतर और सार्थक बातचीत के लिए तंत्र तैयार करना है।

इस अधिसूचना में यह भी जिक्र किया गया है कि समूह नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के लाभों की भी समीक्षा करेगा और अंतराल को भरने के लिए एडवाइजरी जारी करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की दो-टूक, प्रदूषण का समाधान कब तक?

समय सीमा तय करे दिल्ली सरकार

<https://www.livehindustan.com/ncr/story-nhrc-national-human-rights-commission-says-delhi-govt-decide-time-limit-for-solution-of-pollution-crisis-in-ncr-7373306.html>

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह अधिक प्रदूषित स्थानों (हॉटस्पॉट) पर खराब वायुगुणव गु ता के कारणों का हल खोजने के लिए एक समयसीमा तय करे। साथ ही आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से 'लैंडफिल' के लिए वैकल्पिक जगहों के बारे में भी सवाल किया। मानवाधिकार आयोग ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर मिली रिपोर्टों के आलोक में तीसरी सुनवाई की। इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल रहे।

समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकार आयोग की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह हॉटस्पॉट में खराब वायुगुणव गु ता के कारणों का हल निकालने के लिए एक समयसीमा तय करे। आयोग ने यह भी पूछा है कि दिल्ली सरकार बताए कि यह कब तक सामान्य होगा। आयोग ने यह भी जानना चाहा कि कचरा फैकने और स्वच्छता को लेकर वैकल्पिक लैंडफिल स्थानों की क्या व्यवस्था की गई है। आयोग ने मामले में रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है। वहीं समाचार एजेंसी वार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने पराली, धूल, सीवेज कचरे में अस्पताल के प्रबंधन द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कुछ कदमों पर गौर किया। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि उनके बीच के अंतर को दूर करने के लिए एक रणनीतिक योजना की जरूरी है। नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ स्वच्छ हवा और वातावरण प्रदान करने के लिए नीतियां और उनका कार्यान्वयन जरूरी है।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि पंजाब सरकार को पराली की कटाई और निपटान के लिए गरीब किसानों के लिए समर्पित मशीनें रखनी होंगी। मालूम हो कि दिल्ली की वायुगुणव गु ता 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सुबह नौ बजे वायुगुणव गु ता सूचकांक (एक्यूआई) 275 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को इस मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम है।

बच्चों की पढ़ाई को लेकर NHRC ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

<https://jantaserishta.com/local/punjab/nhrc-issues-notice-to-punjab-government-regarding-childrens-education-1761380>

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने फिरोजपुर जिला के सीमावर्ती इलाकों के बच्चों को शिक्षा की उचित सुविधा नहीं मिलने पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।

एनएचआरसी ने बयान जारी कर बताया कि आयोग ने पंजाब के कलुवारा गांव के छात्रों की दुर्दशा के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया विशेषकर उन लड़कियों के बारे में जिन्हें पहले सतलुज नदी के कीचड़ भरे किनारों पर पैदल चलना पड़ता है और फिर राज्य के फिरोजपुर जिला के गट्टी राजोके क्षेत्र में स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचने से पहले पाकिस्तान के साथ सीमा पर और 4 किलोमीटर चलने के लिए एक बरही (एक लकड़ी की नाव) पर सवार होकर नदी पार करनी पड़ती है।

आयोग ने बताया कि समाचार रिपोर्ट ने आगे खुलासा किया कि कलुवारा तीन ओर से नदी से तथा चौथी ओर से सीमा बाड़ से घिरा हुआ है। यह भी कहा गया है कि भारी बारिश के दौरान, नदी के कारण खेतों और घरों में बाढ़ का पानी भर जाता है और यहां के निवासियों को अपनी छतों पर एक साथ दिन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गांव में 50 परिवार रहते हैं और केवल एक प्राथमिक विद्यालय है। उच्च शिक्षा के लिए स्कूलों तक पहुँचने में अत्यधिक कठिनाइयों के कारण प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली अधिकांश लड़कियाँ पांचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं।

बयान में कहा गया कि आयोग ने पाया कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री यदि सत्य है, तो छात्रों के शिक्षा के अधिकार के साथ-साथ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन और सम्मान के अधिकार के प्रति राज्य के अधिकारियों की उदासीनता से संबंधित मुद्दों को उठाती है। राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे और उन्हें गरिमा के साथ रहने का वातावरण प्रदान करके उनके मानवाधिकारों की रक्षा करे।

NHRC ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया, सफाईकर्मियों की ...

<https://www.navyugsandesh.com/nhrc-issues-notice-to-tamil-nadu-government-case-of-death-of-scavengers/>

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तमिलनाडु में तीन सफाई कर्मियों की कथित मौत के मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। गत 15 नवंबर को तमिलनाडु के करूर जिले के गांधी नगर इलाके में एक निर्माणाधीन घर में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान तीन कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गयी थी। आयोग ने घटना की मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और करूर के नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया है तथा मामले पर रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है। एनएचआरसी ने मुख्य सचिव से संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी/जवाबदेही तय करने के संबंध में 'कार्रवाई रिपोर्ट' प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जिन्होंने निर्माण स्थल पर सेप्टिक टैंक की सफाई का जिम्मा सौंपा था। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को प्रदान किए गए मुआवजे और पुनर्वास के विवरण भी मांगा है।

बयान के अनुसार रिपोर्ट में सीवर/सेप्टिक टैंक आदि की खतरनाक सफाई में शामिल श्रमिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जागरूकता और संवेदीकरण शिविरों के साथ-साथ ऐसे सफाई कर्मचारियों के लिए शुरू की गई या शुरू की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

बयान में कहा गया है कि 'कार्रवाई रिपोर्ट' में एनएचआरसी द्वारा पिछले साल 24 सितंबर को खतरनाक सफाई में लगे व्यक्ति के मानवाधिकारों की सुरक्षा और उसके परिणाम के बारे में जारी की गई सलाह का कार्यान्वयन भी शामिल होना चाहिए।

राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी की स्थिति, गिरफ्तारी, यदि कोई हो तो रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। क्या सुरक्षा उपकरणों के बिना निर्माणाधीन घर में सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मृतक श्रमिकों को शामिल करने में शामिल निजी या सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304-ए को लागू करके मौत का कारण बनने में योगदान करने योग्य लापरवाही को शामिल किया गया है।

नगरपालिका आयुक्त को सफाई के दौरान सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने में श्रमिकों को सक्षम नहीं करने तथा उनके खिलाफ प्रचलित सेवा नियमों के अनुसार शुरू

की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण मौत का कारण बनने वाली लोक सेवकों को निर्दिष्ट करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आयोग ने कहा है कि किसी भी स्वच्छता कार्य या खतरनाक सफाई कार्य के मामले में, स्थानीय प्राधिकरण और ठेकेदार/नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।



एनएचआरसी का कोर समूह गठित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने मानवाधिकारों और गैर सरकारी संगठनों का कोर समूह गठित किया है। एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गई।

पुनर्गठित 13 सदस्यीय दल में पूर्व भाजपा विधायक तथा पद्मश्री सम्मान प्राप्त जितेंद्र सिंह शंटी, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के निदेशक सुहास चकमा और पूर्व राजदूत बी मुखर्जी शामिल हैं।

एनएचआरसी ने कोर समूह गठित किया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने मानवाधिकारों और गैर सरकारी संगठनों का कोर समूह गठित किया है। एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गई। पुनर्गठित 13 सदस्यीय दल में पूर्व भाजपा विधायक तथा पद्मश्री सम्मान प्राप्त जितेंद्र सिंह शंटी, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) के निदेशक सुहास चकमा और पूर्व राजदूत बी मुखर्जी शामिल हैं।